

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
2-सुभाष रोड, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

फोन नं० (0135) - 2712055, 2713551
फैक्स नं० (0135) - 2712014, 2713724

संख्या 1006 / 25-XXV-2 (2-4) / 2004

देहरादून : दिनांक 28 मार्च, 2008

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषय:- वर्ष-2001 की जनसंख्या के आधार लोक सभा / विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन,
अधिसूचना का प्रेषण।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक परिसीमन आयोग के पत्र संख्या-282/DEL2008(A) दिनांक 11 मार्च, 2008 एवं पत्र संख्या-282/DEL2008(A) दिनांक 18 मार्च, 2008 के साथ प्राप्त अधिसूचना संख्या-1, 2008 दिनांक 14 जनवरी, 2008 एवं अधिसूचना संख्या-250 दिनांक 19 फरवरी, 2008 तथा अधिसूचना संख्या-255 दिनांक 21 फरवरी, 2008 की प्रति प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 के दूसरे परन्तुक और अनुच्छेद 170 के खण्ड (3) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना में इंगित सारिणी के भाग क में राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों की बावत परिसीमन अधिनियम-2002 की धारा-8 और धारा-9 के अनुसार परिसीमन आयोग द्वारा अधिसूचित पुनः समायोजन प्रभावी होने की तारीख 20 मार्च, 2008 विनिर्दिष्ट की गई है।

कृपया तदनुसार प्राप्ति स्वीकार करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्नक-यथोक्त।

भवदीया,


(राधा रतूड़ी)

सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

DELIMITATION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi - 110001

NO. 282/DEL2008 (A)

Dated: 11th March, 2008J.A. CEO To(ii) The State Election Commissioners,
(As per list)(i) The Chief Electoral Officers,
(As per list)

Subject:

Delimitation (Amendment) Ordinance 2008, and Notification Dated 19th Feb, 2008 regarding implementation of the Commission's Order pertaining to delimitation of Constituencies.

18/3/08

Sir/ Madam

As you are aware that the Delimitation Commission has completed the delimitation exercises in respect of 25 States / UTs. The President of India on 14th January, 2008 promulgated an Ordinance namely the Delimitation (Amendment) Ordinance, 2008 amending the Delimitation Act, 2002. Vide Notification Dated 19th Feb, 2008 the Government has published Presidential Order under Articles 82 and 170 (3) of the Constitution implementing the Delimitation Commission's order in respect of 24 States / UTs. The Delimitation Order made by the Delimitation Commission in respect of the State of Jharkhand has been nullified under Section 10 B of the Delimitation Act, 2002. The Delimitation process in the States of Assam, Arunachal Pradesh, Manipur and Nagaland has been deferred by the President in exercise of the powers under Section 10 A of the Delimitation Act, 2002, as amended by Delimitation (Amendment) Ordinance, 2008 (No. 1 of 2008) from the purview of the present delimitation exercise.

A copy each of the said Ordinance and Notification is forwarded herewith for your information and record.

Kindly acknowledge.

उपसचिव (निदेश)

18/3/08

Yours faithfully,

A.N. Das
(A.N. Das)

UNDER SECRETARY

S.O.

18/3/08
(डा.एस.एस. कन्वाल)
असिस्ट-निर्वाहक



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 1

PART II — Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 1] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 14, 2008 / पोष 24, 1929
No. 1] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 14, 2008 / PAUSA 24, 1929 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, the 14th January, 2008/Pausa 24, 1929 (Saka)

THE DELIMITATION (AMENDMENT) ORDINANCE, 2008

No. 1 of 2008

Promulgated by the President in the Fifty-eighth Year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Delimitation Act, 2002.

WHEREAS Parliament is not in session and the President is satisfied that circumstances exist which render it necessary for her to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 123 of the Constitution, the President is pleased to promulgate the following Ordinance:—

1. (1) This Ordinance may be called the Delimitation (Amendment) Ordinance, 2008.

(2) It shall come into force at once.

2. In section 10 of the Delimitation Act, 2002 (hereinafter referred to as the principal Act),—

(i) in sub-section (4), the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that nothing in this sub-section shall apply to the delimitation orders published in relation to the State of Jharkhand.”;

(ii) in sub-section (6), for the words “within two years of the constitution of the Commission”, the words “within a period not later than 31st day of July, 2008” shall be substituted.

Short title
and
commencement.

Amendment
of section 10.

रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 250]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 19, 2008/माघ 30, 1929

No. 250]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 19, 2008/MAGHA 30, 1929

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2008

का.आ. 382(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

आदेश

संविधान (चौदावीं संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा यथासंशोधित संविधान के अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170(3) के उपबंधों के अधीन, संसद् ने परिसीमन अधिनियम, 2002 अधिनियमित किया तथा लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों के लिए प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन को वर्ष, 2001 में की गई जनगणना में अभिनिरिचित किए गए जनगणना के आंकड़ों के आधार पर पुनः समायोजित करने के लिए परिसीमन आयोग स्थापित किया गया था [जैसा कि संविधान (सत्तासीमा) संशोधन अधिनियम, 2003 के अधीन परिकल्पित है:]

और, परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) की धारा 8 और धारा 9 के अधीन परिसीमन आयोग द्वारा 25 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की बाबत संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित अंतिम आदेश कर दिए गए हैं और ये राजपत्र में प्रकाशित कर दिए गए थे;

और, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें भारत की एकता और अखंडता को खतरा होने की संभावना है और शांति तथा लोक व्यवस्था को गंभीर खतरा है, परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) की धारा 10क की उप-धारा (i) के अधीन भारत के राजपत्र में प्रकाशित क्रमशः आदेश संख्या का.आ. 283(अ), आदेश सं. का.आ. 284(अ), आदेश सं. का.आ. 285(अ) तथा आदेश सं. का.आ. 286(अ), तारीख 8 फरवरी, 2008 के द्वारा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर राज्यों में परिसीमन कार्रवाई को आस्थगित कर दिया है ;

और, परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 10ख के अधीन झारखण्ड राज्य की बाबत परिसीमन आयोग द्वारा किए गए अंतिम आदेशों को, उस राज्य में होने वाले लोक सभा या विधान सभा के लिए प्रत्येक निर्वाचन के संबंध में वर्ष 2026 तक आकृत कर दिया गया है।

और, मेघालय तथा त्रिपुरा राज्यों की विधान सभाओं की अवधि क्रमशः 10 मार्च, 2008 और 19 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाली है तथा इन राज्यों में नई विधान सभाओं का गठन करने के लिए, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 के अनुसार उक्त नियत तारीखों के भीतर किसी भी समय साधारण निर्वाचन कराना आवश्यक है ;

और, मेघालय तथा त्रिपुरा की विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचनों के लिए निर्वाचन कार्यक्रम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अधीन निर्वाचन आयोग द्वारा नियत समय के भीतर पूर्वोक्त राज्यों में नए विधान सभाओं के गठन के लिए संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 के अनुसार अधिसूचित करा दिया गया है ;

अतः, अब, मैं, प्रतिभा देवीसिंह पार्टील, भारत की राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 82 के दूसरे परंतुक और अनुच्छेद 170 के खंड (3) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,—

- (i) इस आदेश की तारीख को, उस तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट करता हूँ, जिसको नीचे सारणी के भाग क में राज्य संघ राज्यक्षेत्र के नाम के सामने विनिर्दिष्ट संबंधित आदेश सं. द्वारा परिसीमन आयोग द्वारा अधिसूचित परिसीमन आदेशों में दिए गए 22 राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों की बाबत परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 8 और धारा 9 के निबंधनों के अनुसार परिसीमन आयोग द्वारा अधिसूचित पुनःसमायोजन प्रभावी होंगे; और
- (ii) 20 मार्च, 2008 को, उस तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट करती हूँ, जिसको नीचे सारणी के भाग ख में राज्यों के नाम के सामने विनिर्दिष्ट संबंधित आदेश सं. द्वारा परिसीमन आयोग द्वारा अधिसूचित परिसीमन आदेशों में दिए गए शंख त्रिपुरा और मेघालय दो राज्यों की बाबत उक्त अधिनियम की धारा 8 और धारा 9 के निबंधनों के अनुसार परिसीमन आयोग द्वारा अधिसूचित पुनःसमायोजन प्रभावी होंगे।

सारणी

भारत के परिसीमन आयोग द्वारा जारी किए गए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड (3), उपखंड (iii) में प्रकाशित परिसीमन आदेशों के खीरे

क्रम सं.	राज्य का नाम	आदेश सं. (परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 8 के अधीन जारी) और तारीख	आदेश सं. (परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 9 के अधीन जारी) और तारीख	शुद्धिपत्र/पूरक आदेश, यदि कोई हों, और उनकी तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
भाग क				
1.	गोवा	आदेश सं. 2 आ. सं. 193(अ) तारीख 8-11-2004	आदेश सं. 5 आ. सं. 9(अ) तारीख 31-3-2005	—
2.	पांडिचेरी	आदेश सं. 1 आ. सं. 190(अ) तारीख 8-10-2004	आदेश सं. 6 आ. सं. 10(अ) तारीख 31-3-2005	—
3.	मिजोरम	आदेश सं. 7 आ. सं. 13(अ) तारीख 13-4-2005	आदेश सं. 10 आ. सं. 27(अ) तारीख 27-5-2005	शुद्धि-पत्र तारीख 11-7-2005 आ. सं. 34(अ)
4.	केरल	आदेश सं. 4 आ. सं. 6(अ) तारीख 23-3-2005	आदेश सं. 9 आ. सं. 29(अ) तारीख 31-5-2005	आदेश संख्या 55 आ. सं. 2(अ) तारीख 16-1-2008
5.	राजस्थान	आदेश सं. 12 आ. सं. 35(अ) तारीख 8-8-2005	आदेश सं. 16 आ. सं. 4(अ) तारीख 25-1-2006	—
6.	पश्चिमी बंगाल	आदेश सं. 11 आ. सं. 37(अ) तारीख 8-8-2005	आदेश सं. 18 आ. सं. 9(अ) तारीख 15-2-2006	—
7.	छत्तीसगढ़	आदेश सं. 14 आ. सं. 61(अ) तारीख 12-12-2005	आदेश सं. 24 आ. सं. 52(अ) तारीख 2-6-2006	शुद्धि-पत्र तारीख 25-8-2006 आ. सं. 71(अ)
8.	पंजाब	आदेश सं. 15 आ. सं. 63(अ) तारीख 12-12-2005	आदेश सं. 22 आ. सं. 58(अ) तारीख 19-6-2006	—

[भाग II—खण्ड 3(II)]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.	महाराष्ट्र	आदेश सं. 2. आ. सं. 24(अ) तारीख 28-3-2006	आदेश सं. 26 आ. सं. 64(अ) तारीख 31-7-2006	—
10.	सिक्किम	आदेश सं. 13 आ. सं. 42(अ) तारीख 29-8-2005	आदेश सं. 28 आ. सं. 80(अ) तारीख 4-9-2006	—
11.	दिल्ली	आदेश सं. 17 आ. सं. 5(अ) तारीख 27-1-2006	आदेश सं. 30 आ. सं. 85(अ) तारीख 20-9-2006	—
12.	गुजरात	आदेश सं. 23 आ. सं. 38(अ) तारीख 19-5-2006	आदेश सं. 33 आ. सं. 121(अ) तारीख 12-12-2006	—
13.	उड़ीसा	आदेश सं. 19 आ. सं. 19(अ) तारीख 17-3-2006	आदेश सं. 32 आ. सं. 122(अ) तारीख 15-12-2006	—
14.	उत्तर प्रदेश	आदेश सं. 27 आ. सं. 62(अ) तारीख 28-7-2006	आदेश सं. 34 आ. सं. 123(अ) तारीख 18-12-2006	आदेश सं. 41 आ. सं. 50(अ) तारीख 30-3-2007
15.	उत्तरांचल	आदेश सं. 29 आ. सं. 78(अ) तारीख 4-9-2006	आदेश सं. 35 आ. सं. 124(अ) तारीख 26-12-2006	—
16.	हिमाचल प्रदेश	आदेश सं. 20 आ. सं. 22(अ) तारीख 27-3-2006	आदेश सं. 36 आ. सं. 2(अ) तारीख 10-1-2007	—
17.	हरियाणा	आदेश सं. 31 आ. सं. 105(अ) तारीख 30-10-2006	आदेश सं. 39 आ. सं. 18(अ) तारीख 15-2-2007	—
18.	आंध्र प्रदेश	आदेश सं. 37 आ. सं. 7(अ) तारीख 22-1-2007	आदेश सं. 46 आ. सं. 78(अ) तारीख 31-5-2007	—
19.	मध्य प्रदेश	आदेश सं. 38 आ. सं. 4(अ) तारीख 19-1-2007	आदेश सं. 45 आ. सं. 70(अ) तारीख 14-5-2007	—
20.	कर्नाटक	आदेश सं. 42 आ. सं. 46(अ) तारीख 23-3-2007	आदेश सं. 49 आ. सं. 90(अ) तारीख 2-7-2007	—
21.	तमिलनाडु	आदेश सं. 43 आ. सं. 52(अ) तारीख 5-4-2007	आदेश सं. 52 आ. सं. 108(अ) तारीख 13-8-2007	—
22.	बिहार	आदेश सं. 48 आ. सं. 79(अ) तारीख 11-6-2007	आदेश सं. 54 आ. सं. 111(अ) तारीख 17-8-2007	—

4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		भाग ख		
23.	त्रिपुरा	आदेश सं. 3 आ. सं. 3(अ) तारीख 28-2-2005	आदेश सं. 8 आ. सं. 18(अ) तारीख 12-5-2005	—
24.	मेघालय	आदेश सं. 40 आ. सं. 28(अ) तारीख 12-3-2007	आदेश सं. 50 आ. सं. 91(अ) तारीख 2-7-2007	शुद्धि-पत्र तारीख 2-7-2007 आ. सं. 89(अ) शुद्धि-पत्र तारीख 30-7-2007 आ. सं. 104(अ)

19 फरवरी, 2008

भारत की राष्ट्रपति

[फा. सं. एच.-11019(10)/2007-वि. II]

कै. डी. सिंह, सचिव



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 255]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 21, 2008/फाल्गुन 2, 1929

No. 255]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 21, 2008/PHALGUNA 2, 1929

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 21st February, 2008

S.O. 387(E). — In the English version of the notification of the Government of India in the Ministry of Law and Justice (Legislative Department), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated 19th February, 2008 *vide* number S.O. 382(E) of the same date, specifying the date on which the new Delimitation Orders notified by the Delimitation Commission under the Delimitation Act, 2002 shall take effect in terms of articles 82 and 170 of the Constitution,—

At page 4, line 24, *for* “expired”, *read* “expire”;

At page 5, line 21, against S.No. 2 relating to Pondicherry, in column 4, *for* “Order No. 6, O.N. 6(E),” *read* “Order No. 6. O.N. 10(E).”

[F.No. H-11019(10)/2007-Leg. II]
Dr. SANJAY SINGH, Jt. Secy. & LC

BY SPEED POST

DELIMITATION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi.

N0.282/DEL/2008(A)

Dated: 18th March, 2008

To

- (i) The State Election Commissioners,
(As per list).
- (ii) The Chief Electoral Officers,
(As per list).

Subject:- Delimitation of Assembly and Parliamentary Constituencies on the basis of Census Figures – 2001 -- forwarding of Corrigendum dated 21st February, 2008 – regarding.

Sir/Madam,

In continuation of the of the Commission's letter of even number dated 11th March, 2008, I am directed to forward a copy of the Corrigendum dated 21st February, 2008 for your kind perusal and information.

Kindly acknowledge the receipt.

Yours faithfully,


(A.N. Das)

UNDER SECRETARY

15.	Uttaranchal	Order No. 29, O.N. 78(E) dated 04-09-2006	Order No. 35, O.N. 124(E) dated 28-12-2006	—
16.	Himachal Pradesh	Order No. 20, O.N. 22(E) dated 27-03-2006	Order No. 36, O.N. 2(E) dated 10-01-2007	—
17.	Haryana	Order No. 31, O.N. 105(E) dated 30-10-2006	Order No. 39, O.N. 18(E) dated 15-02-2007	—
18.	Andhra Pradesh	Order No. 37, O.N. 7(E) dated 22-01-2007	Order No. 46, O.N. 78(E) dated 31-05-2007	—
19.	Madhya Pradesh	Order No. 38, O.N. 4(E) dated 19-01-2007	Order No. 45, O.N. 70(E) dated 14-05-2007	—
20.	Karnataka	Order No. 42, O.N. 46(E) dated 23-03-2007	Order No. 49, O.N. 90(E) dated 02-07-2007	—
21.	Tamil Nadu	Order No. 43, O.N. 52(E) dated 05-04-2007	Order No. 52, O.N. 108(E) dated 13-08-2007	—
22.	Bihar	Order No. 48, O.N. 79(E) dated 11-06-2007	Order No. 54, O.N. 111(E) dated 17-08-2007	—

PART-B

23.	Tripura	Order No. 3, O.N. 3(E) dated 28-02-2005	Order No. 8, O.N. 18(E) dated 12-05-2005	—
24.	Meghalaya	Order No. 40, O.N. 28(E) dated 12-03-2007	Order No. 50, O.N. 91(E) dated 02-07-2007	Corrigendum dated 02-07-2007, O.N. 89(E); Corrigendum dated 30-07-2007, O.N. 104(E)

19th February, 2008

PRESIDENT OF INDIA

[F.No. H-11019(10)/2007-Leg. II]

K. D. SINGH, Secy.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the second proviso to article 32 and the second proviso to clause (3) of article 170 of the Constitution, I, Pratibha Devisingh Patil, President of India, hereby specify—

- (i) the date of this Order as the date on which readjustments notified by the Delimitation Commission in terms of Sections 8 and 9 of the Delimitation Act, 2002 in respect of the 22 States/Union Territories, given in the Delimitation Orders notified by the Delimitation Commission vide respective O.N. Numbers specified against the name of the State/Union Territory in PART-A of the TABLE below shall take effect; and
- (ii) the 20th day of March, 2008 as the date on which readjustments notified by the Delimitation Commission in terms of Sections 8 and 9 of the said Act in respect of the remaining 2 States of Tripura and Meghalaya, given in the Delimitation Orders notified by the Delimitation Commission vide respective O.N. Numbers specified against the name of the States in PART-B of the TABLE below shall take effect.

TABLE

Details of the Delimitation Orders issued by the Delimitation Commission and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (iii)

Sl. No.	Name of the State	Order No. (issued under Section 8 of the Delimitation Act, 2002) and Date	Order No. (issued under Section 9 of the Delimitation Act, 2002) and Date	Corrigendum/Supplementary Orders, if any and their date
1	2	3	4	5
PART-A				
1.	Goa	Order No. 2, O.N. 193(E) dated 08-11-2004	Order No. 5, O.N. 9(E) dated 31-03-2005	—
2.	Pondicherry	Order No. 1, O.N. 190(E) dated 08-10-2004	Order No. 6, O.N. 6(E) dated 31-03-2005	—
3.	Mizoram	Order No. 7, O.N. 13(E) dated 13-04-2005	Order No. 10, O.N. 27(E) dated 27-05-2005	Corrigendum dated 11-07-2005 O.N. 34(E)
4.	Kerala	Order No. 4, O.N. 6(E) dated 23-03-2005	Order No. 9, O.N. 29(E) dated 31-05-2005	Order No. 55, O.N. 2(E) dated 16-01-2008
5.	Rajasthan	Order No. 12, O.N. 35(E) dated 08-08-2005	Order No. 16, O.N. 4(E) dated 25-01-2006	—
6.	West Bengal	Order No. 11, O.N. 37(E) dated 08-08-2005	Order No. 18, O.N. 9(E) dated 15-02-2006	—
7.	Chhattisgarh	Order No. 14, O.N. 61(E) dated 12-12-2005	Order No. 24, O.N. 52(E) dated 02-06-2006	Corrigendum dated 25-08-2006, O.N. 71(E)
8.	Punjab	Order No. 15, O.N. 63(E) dated 12-12-2005	Order No. 22, O.N. 58(E) dated 19-06-2006	—
9.	Maharashtra	Order No. 21, O.N. 24(E) dated 28-03-2006	Order No. 26, O.N. 64(E) dated 31-07-2006	—
10.	Sikkim	Order No. 13, O.N. 42(E) dated 29-08-2005	Order No. 28, O.N. 80(E) dated 04-09-2006	—
11.	Delhi	Order No. 17, O.N. 5(E) dated 27-01-2006	Order No. 30, O.N. 85(E) dated 20-09-2006	—
12.	Gujarat	Order No. 23, O.N. 38(E) dated 19-05-2006	Order No. 33, O.N. 121(E) dated 12-12-2006	—
13.	Orissa	Order No. 19, O.N. 19(E) dated 17-03-2006	Order No. 32, O.N. 122(E) dated 15-12-2006	—
14.	Uttar Pradesh	Order No. 27, O.N. 62(E) dated 28-07-2006	Order No. 34, O.N. 123(E) dated 18-12-2006	Order No. 41, O.N. 50(E) dated 30-03-2007

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 2008

S.O. 382(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

ORDER

Whereas under the provisions of article 82 and article 170 (3) of the Constitution, as amended by the Constitution (Eighty-fourth Amendment) Act, 2001, Parliament enacted the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002) and a Delimitation Commission has been set up to readjust the division of each State and Union Territory into territorial constituencies for the purpose of elections to the House of the People and to the State Legislative Assemblies on the basis of census figures as ascertained at the census taken in the year 2001 [as envisaged under the Constitution (Eighty-seventh) Amendment Act, 2003];

And whereas, the final orders relating to the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies in respect of 25 States and the Union Territories have been made by the Delimitation Commission under Sections 8 and 9 of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002) and were published in the Official Gazettes;

And whereas on being satisfied that a situation has arisen where unity and integrity of India is likely to be threatened and there is a serious threat to peace and public order the delimitation exercise in the States of Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland and Manipur have been deferred under sub-section (1) of Section 10A of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002) *vide* Orders published in the Gazette of India having numbers S.O. 283(E), S.O. 284(E), S.O. 285(E) and S.O. 286(E), dated 8th February, 2008 respectively;

And whereas under Section 10B of the Delimitation Act, 2002 the final orders made by the Delimitation Commission in respect of the State of Jharkhand have been nullified until the year 2026 in relation to every election to the House of the People or to the Legislative Assembly to be held in that State;

And whereas the terms of the Legislative Assemblies of the States of Meghalaya and Tripura are due to expired on 10th March, 2008 and 19th March, 2008 respectively, and it is necessary to hold general elections to constitute the new Legislative Assemblies in these States at any time within the said due dates as per the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976;

And whereas the election schedule for general elections to the Legislative Assemblies of Meghalaya and Tripura has been notified by the Election Commission under the Representation of the People Act, 1951 as per the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976 for constituting the new Assemblies in the aforesaid States within the stipulated time;